

"युद्ध अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेदेल फिलिप्स

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 3 जून 2026 बुधवार

सम्पादकीय

खाद का गहराता संकट

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल और ईंधन की कीमतों में भारी उछाल के कारण देश में खाद (यूरिया, डीएपी, एनपीके) का गहराता संकट एक बड़ी चुनौती बन गया है। किसानों को बुवाई के समय लंबी लाइनों में लगने और बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम एशिया के तनाव और आपूर्ति शृंखला में बाधाओं के कारण विदेशों से आयात होने वाले कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू मांग और उपलब्धता के बीच असंतुलन के कारण ऐन बुवाई के समय सोसायटियों और दुकानों पर स्टॉक खत्म हो जाता है। एनपीके जैसी जटिल खादों की कीमतों में हाल ही में लगभग 200 से 400 प्रति बोरी की वृद्धि दर्ज की गई है, जो यूरिया और डीएपी की महंगाई का संकेत है। सही समय पर खाद न मिलने के कारण कई राज्यों में अव्यवस्था, किसानों के बीच झड़प और कालाबाजारी की शिकायतें बढ़ रही हैं। खाद महंगे होने से छोटे और सीमांत किसानों का कृषि बजट बिगड़ रहा है। समय पर उर्वरक (डीएपी, यूरिया) न मिलने से रबी और खरीफ़ दोनों फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है।

यह अस्थिर है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति में कठिनाई और उनके मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार न खेत बनाओ अभियान शुरू किया। इस अभियान को शुरू करने के पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों और किसान संगठनों से गहरा संवाद किया, उससे यह होता चलता है कि वे इस अभियान को वास्तव में सफल बनाए हुए देखना चाहते हैं। ऐसे किसी अभियान की सफलता जन भागीदारी और जागरूकता के माध्यम से ही संभव है। नि:संदेह इस अभियान में केंद्र सरकार को राज्यों का सक्रिय सहयोग चाहिए होगा।

इसी तरह यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि आम किसान यह समझें कि रासायनिक उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग केवल खेती की लागत ही नहीं बढ़ाता, बल्कि खेतों की मिट्टी की उर्वर क्षमता को भी कम करता है। इसके अतिरिक्त भूजल भी दूषित होता है। एक ऐसे समय जब जलवायु बदल रही है, तब उर्वरकों का असंतुलित उपयोग खेती के सामने गंभीर चुनौती बन रहा है।

समस्या यह है कि औसत किसान यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल अंततः उनके लिए घाटे का सीधा ही सिद्ध होता है, क्योंकि खेतों में तो फसल अच्छी होती है, लेकिन समय के साथ खेतों की मिट्टी दूषित हो जाने के कारण उपज प्रभावित होती है।

वैसे तो प्रधानमंत्री ऐसी अपील करते रहे हैं कि किसान रासायनिक उर्वरकों का सही उपयोग करने के लिए खेतों की मिट्टी का परीक्षण कराएं और जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दें, लेकिन इसका बाद भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए और रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग जारी है। इसका एक कारण उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी भी है। एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये उर्वरक सब्सिडी पर खर्च किए।

इस वर्ष यह खर्च कहीं अधिक बढ़ने का आसार है। क्योंकि अधिकतर उर्वरकों का आयात किया जाता है और अमेरिका-ईरान तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा की मांने तो जहां दो बोरी उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता होती है, वहां किसान चार बोरी का उपयोग करते हैं।

वास्तव में जब भी कोई वस्तु सब्सिडी के चलते कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है तो उसका अनावश्यक उपयोग बढ़ जाता है। तथ्य यह भी है कि किसानों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने वाले उर्वरक की कालाबाजारी भी होती है, क्योंकि उसका इस्तेमाल औद्योगिक रसायन के रूप में भी होता है। मूल प्रश्न यह कि आखिर किसानों को खाद संकट के बीच ही इससे होने वाले नुकसान क्यों समझाया जा रहे हैं। सच तो ये है कि खाद की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन पर भी असर पड़ेगा और देश को अन्न संकट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा हो कि सुझाव की जगह सरकार सार्थक समाधान की ओर आगे बढ़े।

चीन की दूरदृष्टि से सबक लेना समय की जरूरत

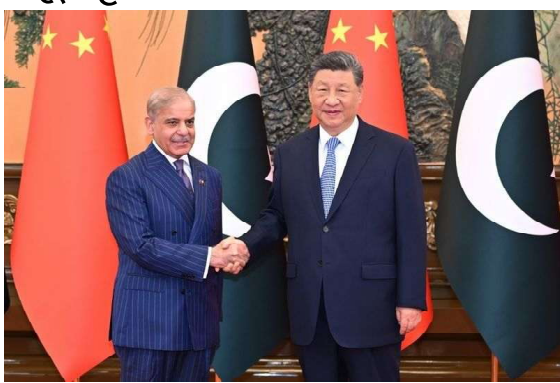


—गुरुबचन जगत—

दुनिया में तेज बदलावों व हालिया युद्धों से उपजे ऊर्जा संकट और चीन-पाक के गडजोड़ जैसी चुनौतियों से पार पाने को देश को सुझावन नेतृत्व और कुटनीति की जरूरत है। दूरदर्शी योजनाओं से चीन ने ऊर्जा, रैपर अर्थ, इवी और बैटरी क्षेत्रों में जबरदस्त क्षमता हासिल की। वहीं भारत ऊर्जा के लिए आयातों पर निर्भर है।

कूममर न्यूज की 28 जनवरी, 2026 की खबर के अनुसार, चीन ने पिछले साल सभी तकनीकी क्षेत्रों में 543 गीगावाट जितनी सई बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारत में 2024 के आखिर तक के पैदा हुए कुल बिजली उत्पादन से 12 प्रतिशत ज्यादा है। चीन की इस बढ़ती रफ्तार ने 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा अग्रय ऊर्जा का था, जिसमें सौर व पवन ऊर्जा शामिल है। वहीं यूरोप एनई-इमर्सन एन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार है (लगभग 14 अरब बैरल)। रिपोर्ट्स कि उसने 2025 में अपने तेल भंडारण में काफी वृद्धि की, और रूस, ईरान और वेनेजुएला से रियायती दरों पर करोड़ों बैरल तेल खरीदा। जबकि भारत के पास सिर्फ 21 मिलियन बैरल का तेल भंडार था।

पिछले कुछ दशकों में, चीन ने रैपर अर्थ मिनरल्स, इलेक्ट्रिक यान (ईवी) उत्पादन, लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन और क्वीन एनर्जी के क्षेत्र में अपनी जबरदस्त रणनीतिक बढ़त बनाई है। चीनी लोग इस समृद्धी मूल्य संचयन रणनीति में अब दुनिया में अग्रणी हैं। ऐसा कर उन्होंने न केवल जीआयएम इंधन पर निर्भरता कम की और प्रदूषण घटाया बल्कि जीआयएम इंधन से दूर हटती दुनिया के दौर में अपनी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति भी बना ली। रैपर अर्थ मिनरल्स, ईवी



निर्माण, बैटरी उत्पादन व स्वच्छ ऊर्जा की यह तिकड़ी, किसी अर्थव्यवस्था की जीव्याम ईंधन पर निर्भरता खत्म करने का सबसे अग्रिम माध्यम है। यह सब साक्ष्यानी की से गई योजनावदी से हासिल हो पाया, जिससे पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष स्थान दिया गया (अभी वह 15वीं योजना चल रही है)। ये योजनाएं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद (चीनी कोंग्रेस) ने मिलकर बनाती हैं। यह रणनीतिक बदल ही तब करेगी कि देश आगामी 100 साल संकट से कैसे निबटरे। यह उची और नीची महंगाई बढ़ वाले देशों के बीच का फर्क बनाता है, और यह तय करने में एक अग्रिम भूमिका निभाएगा। एक आईएफ डेयु में डेटा सेंटर कहा थापिस्ट होने, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, भंडारण, रैपर अर्थ मिनरल और डेटा सेंटरों के बीच एक रणनीतिक साझ है। बीते साल चीन ने अपने रणनीतिक अरु का इस्तेमाल किया व रैपर अर्थ के नियंत्रण पर रोक लगाकर भारत का ईवी उत्पादन करीब टप कर दिया था (इस क्षेत्र में उसका लगभग एकाधिकार है)।

देश -अपनी सरकारों के जरूरत-भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। ऐसी योजना में वित्त के और मौजूदा अनुभवों का गहराई से विश्लेषण करना शामिल होता है, साथ ही भविष्य के समाहित बदलावों के बारे में भी अनुमान भी लगाए जाते हैं। उपरोक्त

अभयवों के आधार पर, सरकार भविष्य से निबटने को नीतियां बनाती है। जब हम खुद को और अपनी मौजूदा स्थिति को, खासकर ऊर्जा की स्थिति और उसके नतीजों के मामले में, देखते हैं, तो लगता है कि हमने पिछले कुछ दशक में जरूरी तैयारी नहीं की।

चूंकि भारत का एक उदाहरण बहुत कम है, इसलिए यह यकीनी बनाना कठं की सम्भव उपलब्ध है कि आपात स्थिति में निम्नान उपलब्ध है। प्रमाण भंडार बनाए, और इससे भी ज्यादा जरूरी यह कि बड़े पैमाने पर हरिष्ट ऊर्जा अर्थव्यवस्था, ताकि हम आपातित करने अंतर पर बिकल्प निर्भर न रहे। जहां यह बात तालरती देते वाली है कि हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का आधा हिस्सा अब नवीकरणीय स्रोतों से आता है, लेकिन कौनसा आकारित ऊर्जा उत्पादन को हिस्सा अभी भी सबसे अधिक (लगभग 42 प्रतिशत) है। अरुम बात यह है कि यह अभी भी कुल बिजली उत्पादन का 70 प्रतिशत हिस्सा मूज्या खयात है, जबकि भारत ने अभी तक बिजली के उभरती करती आपत क्षमता विसिस्त नहीं की। जबकि चीन ने इस मामले में बहुत काम किया है। यह दशक लगातार उच्च-उपेक्ष मरा रहा है, जब कोइड महामारी, फिर पूर्य यूरोप और पश्चिम एशिया युद्ध जोरि जारी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उदयन। भारत औद्योगिक क्रांति करने से चूक गया था, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। देश 80 और 90 के दशक के जय अलग-अलग देशों के रणनीतिक हित आरुप में टकरा रहे थे, तो ऐसे में एक समझदार और दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है। एआई आधारभूत तंत्र विकास और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक साझेदारियां बनाने में विदेश नीति और कुटनीति की अग्रम भूमिका होगी। आज की तारीख में, यहां तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और डिजिट स्टोरेज के हेतु बैटरी बनाने की हमारी क्षमता चीन से आयातित 'दुर्लभ धातुओं' पर निर्भर है (इस क्षेत्र में भी चीन का लगभग एकाधिकार)। रणनीतिक उद्यमकों की जरूरत हमें चीन से की, और पश्चिमी एशिया में बल रहे युद्ध के कारण स्टूट ऑफ हार्मुजुज के बंद हो जाने से पैदा हुई उर्वरकों और कच्चे तेल की समावित कमी व आपूर्ति शृंखला में कठवादी के रूप में साक्ष दिखती है। हमें मजबूतपन हाथ-पैर मारने पड़े रहे, दूसरों से मदद मांगनी पड़ी। रूस सैन्य और भी समझौता था, चीन की तरह, लेकिन रूस पर प्रतिबंधों का सवाधिक नुकसान हमें उठाटना पड़ा।

शालीन नदी, जो चुपचाप बहती रही

—संदीप सृजन—



भारतीय फिलम संगीत के स्वर्णिम इतिहास का एक और उज्वल अंश था अधिक उपयोग केवल खेती की लागत ही नहीं बढ़ाता, बल्कि खेतों की मिट्टी की उर्वर क्षमता को भी कम करता है। इसके अतिरिक्त भूजल भी दूषित होता है। एक ऐसे समय जब जलवायु बदल रही है, तब उर्वरकों का असंतुलित उपयोग खेती के सामने गंभीर चुनौती बन रहा है।

समस्या यह है कि औसत किसान यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल अंततः उनके लिए घाटे का सीधा ही सिद्ध होता है, क्योंकि खेतों में तो फसल अच्छी होती है, लेकिन समय के साथ खेतों की मिट्टी दूषित हो जाने के कारण उपज प्रभावित होती है। वैसे तो प्रधानमंत्री ऐसी अपील करते रहे हैं कि किसान रासायनिक उर्वरकों का सही उपयोग करने के लिए खेतों की मिट्टी का परीक्षण कराएं और जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दें, लेकिन इसका बाद भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए और रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग जारी है। इसका एक कारण उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी भी है। एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये उर्वरक सब्सिडी पर खर्च किए। इस वर्ष यह खर्च कहीं अधिक बढ़ने का आसार है। क्योंकि अधिकतर उर्वरकों का आयात किया जाता है और अमेरिका-ईरान तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा की मांने तो जहां दो बोरी उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता होती है, वहां किसान चार बोरी का उपयोग करते हैं। वास्तव में जब भी कोई वस्तु सब्सिडी के चलते कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है तो उसका अनावश्यक उपयोग बढ़ जाता है। तथ्य यह भी है कि किसानों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने वाले उर्वरक की कालाबाजारी भी होती है, क्योंकि उसका इस्तेमाल औद्योगिक रसायन के रूप में भी होता है। मूल प्रश्न यह कि आखिर किसानों को खाद संकट के बीच ही इससे होने वाले नुकसान क्यों समझाया जा रहे हैं। सच तो ये है कि खाद की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन पर भी असर पड़ेगा और देश को अन्न संकट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा हो कि सुझाव की जगह सरकार सार्थक समाधान की ओर आगे बढ़े।

किरी विवाद का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की। उनकी सफलता का आधार केवल उनका संगीत था। शायद यही कारण है कि उनके बारे में बात करते समय लोग उनकी गायकी के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व को भी प्रशंसा करते हैं।

समय बदलता गया, संगीत की शैलियां बदलती गईं, नई पीढ़ियां आती गईं लेकिन सुमन कल्याणपुर की आवाज की मधुरता कभी पुरानी नहीं हुई। उनके गीतों में एक ऐसी शाश्वत तानगी है जो हर पीढ़ी को काकर्षित करती है। आज भी जब उनके गीत सुनाई देते हैं तो लगता है मानों किसी पुराने मित्र की आनीय आवाज कानों में गूंज रही हो।

उनके निधन के साथ भारतीय संगीत का एक युग अस्थिर मधुर हुआ है लेकिन उनकी विरासत कभी समाप्त नहीं होगी। वे उन कलाकारों में थीं जिन्होंने यह सिद्ध किया कि महानता की शक्तों के माय को समझने अपने पूरे जीवन में संगीत को पूजा की तरह साया और उसी साधना ने उन्हें अमर बना दिया।

आज जब हम सुमन कल्याणपुर को श्रद्धांजलि देते हैं तो उनके स्वर हमारे भीतर फिर से जीवित हो उठते हैं। वे भले ही भौतिक रूप से हमसे दूर करे गई हैं, लेकिन उनके गीत आज वाली पीढ़ियों तक गुंजते रहेंगे। जब भी कोई संगीत प्रेमी उनका गीत सुनेगा, तब वह केवल एक बुन नहीं सुनेगा बल्कि भारतीय संगीत की उस स्वर्णिम परंपरा को महसूस करेगा जिसका सुमन कल्याणपुर एक अकरंत महत्वपूर्ण अंश हैं।

सुमन कल्याणपुर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची कला को प्रभाव की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने मूल्यों को कारण स्वर अग्र हो जाती है। उनका स्वर आज भी भारतीय संगीत की स्मृतियों में उठी रहत जीवित है जैसे किसी शांत नदी का मधुर कल-कल-कल, जो दिखाने भले न दे लेकिन स्वयं सुनाई देता रहता है। उनकी स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि।

आज जब हम सुमन कल्याणपुर को श्रद्धांजलि देते हैं तो उनके स्वर हमारे भीतर फिर से जीवित हो उठते हैं। वे भले ही भौतिक रूप से हमसे दूर करे गई हैं, लेकिन उनके गीत आज वाली पीढ़ियों तक गुंजते रहेंगे। जब भी कोई संगीत प्रेमी उनका गीत सुनेगा, तब वह केवल एक बुन नहीं सुनेगा बल्कि भारतीय संगीत की उस स्वर्णिम परंपरा को महसूस करेगा जिसका सुमन कल्याणपुर एक अकरंत महत्वपूर्ण अंश हैं।

आज जब हम सुमन कल्याणपुर को श्रद्धांजलि देते हैं तो उनके स्वर हमारे भीतर फिर से जीवित हो उठते हैं। वे भले ही भौतिक रूप से हमसे दूर करे गई हैं, लेकिन उनके गीत आज वाली पीढ़ियों तक गुंजते रहेंगे। जब भी कोई संगीत प्रेमी उनका गीत सुनेगा, तब वह केवल एक बुन नहीं सुनेगा बल्कि भारतीय संगीत की उस स्वर्णिम परंपरा को महसूस करेगा जिसका सुमन कल्याणपुर एक अकरंत महत्वपूर्ण अंश हैं।

आज जब हम सुमन कल्याणपुर को श्रद्धांजलि देते हैं तो उनके स्वर हमारे भीतर फिर से जीवित हो उठते हैं। वे भले ही भौतिक रूप से हमसे दूर करे गई हैं, लेकिन उनके गीत आज वाली पीढ़ियों तक गुंजते रहेंगे। जब भी कोई संगीत प्रेमी उनका गीत सुनेगा, तब वह केवल एक बुन नहीं सुनेगा बल्कि भारतीय संगीत की उस स्वर्णिम परंपरा को महसूस करेगा जिसका सुमन कल्याणपुर एक अकरंत महत्वपूर्ण अंश हैं।

वी.आई.पी. अपराधियों के लिए जेलें होल?

—रजनीश कपूर—

भारत में कानून की समानता का सिद्धांत संविधान का मूल आधार है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सब समान हैं। लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके उलट दिखती है। बलात्कार और हत्या के मामलों में सजा काट रहे डेरा सच्चा सोदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह का मामला इसका स्पष्ट उदाहरण है। रोहतक की सुनारिया जेल, जहां वह बंद है, उनके लिए लगभग होटल जैसी सुविधाओं का केंद्र बन गई है, जबकि आम कड़ी कानून परिस्थितियों में सजा काटते हैं।

उल्टेकानून है कि 2017 में 2 साक्षियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 वर्ष की सजा पाने के बाद राम रहीम रोहतक जेल में बंद हैं। बाद में पत्रकार रामजद जयपति और रजनी सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास भी मिला। जेल में उनके रिश्ते विश्व सी.एल. बोलाबंद पाणी, सत्यम कर्मी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। एक पूर्ण कौमी ने आरोप लगाया कि एक रिश्ते की ओर अन्य कैदियों से ज़्यादा समय मुलाकात के लिए मिलता है। जेल सामग्य कैदियों को मात्र 20 मिनिट मिलते हैं, वहीं राम रहीम को घंटों की छूट दी जाती रही। जेल प्रशासन ने इन आरोपों से इंकार किया लेकिन राम रहीम को सजा काटने के बाद भी कोई संगीत प्रेमी उनका गीत सुनेगा, तब वह केवल एक बुन नहीं सुनेगा बल्कि भारतीय संगीत की उस स्वर्णिम परंपरा को महसूस करेगा जिसका सुमन कल्याणपुर एक अकरंत महत्वपूर्ण अंश हैं।

सुमन कल्याणपुर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची कला को प्रभाव की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने मूल्यों को कारण स्वर अग्र हो जाती है। उनका स्वर आज भी भारतीय संगीत की स्मृतियों में उठी रहत जीवित है जैसे किसी शांत नदी का मधुर कल-कल-कल, जो दिखाने भले न दे लेकिन स्वयं सुनाई देता रहता है। उनकी स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि।

लगेगा। अमेरिका-ईरान युद्ध बंदी वार्ता नाकाम होना हमारे लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा और इससे अफगान-अफगान चम सकती है - ऐसी स्थिति से हम अब तक किसी तरह बचे हुए थे। इसके साथ ही, अमेरिका पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल की पीठ पीछे है, और ईरान के मामले में उस पर एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में भरोसा करता है। आर्थिक सुधारियों से रहल पाने में अमेरिका ने विषय बैंक के जरिए उसकी मदद की है।

भारत की मुश्किलों को और बढ़ाने वाली बात है चीन और पाकिस्तान के बीच के करीबी रिश्ते। चीन की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहाबाज शरीफ का स्वागत राष्ट्रपति श्री दिनकर ने किया, और दोनों के बीच की पहलड़ी से भी ऊंची दास्ती का वचन एक बार फिर दोहराया है। जारी संयुक्त बयान में, लंबे समय से चले आए जम्मू और कश्मीर विवाद को सुलझाने की बात कही गई।

चीन हमारे पूर्वोत्तर में निरंतर बुनियादी ढांचा विकास कर रहा है, खासकर उन इलाकों में जिन पर वह अपना दावा जताता आया है। मणिपुर में पिछले तीन सालों से चले आ रही समस्या और गंगालेड एन रिजॉनर के पुराने नासूत बने हैं कि पूर्वोत्तर में हमारी अपनी स्थिति भी खराब अच्छी नहीं है। बंगालदेश में हाल ही में युवाई गईं नई सरकार ने भी नए नजर रखे हैं। क्योंकि वह पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी नजदीकियां बना रही है, और पूर्वोत्तर में हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने में सक्षम है। इन अवयवों को एक साथ देखें -ऊर्जा की स्थिति, जिसके साथ वैश्व विद्युत विगडने की आवश्यकता है, चीन, पाकिस्तान और बंगालदेश का हमारे प्रति रवैया और हमारी अपनी अदरुमी समझौता- तो इस समय बेहद सुझावन राखेता और उच्च कोटि की कुटनीतिकी की जरूरत है।

इसी तरह, अब हम ईरान से भी तेल नहीं मिल पा रहा है। हमारी भंडारण क्षमता भी सीमित है, और हमने हाल ही में यूएई के साथ मिलकर बड़े-बड़े तेल भंडार बनाने का समझौता किया है, लेकिन ईरान फलीभूत होने में अभी काफी समय

करने के लिए पूरे देश का एकजुट रहना जरूरी है। इस फलक की शुभधातु भारत सरकार के नेतृत्व से ही चाहिए।

लेखक मणिपुर के राज्यपाल एवं जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक रहे हैं।



अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल और ईंधन की कीमतों में भारी उछाल के कारण देश में खाद (यूरिया, डीएपी, एनपीके) का गहराता संकट एक बड़ी चुनौती बन गया है। किसानों को बुवाई के समय लंबी लाइनों में लगने और बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम एशिया के तनाव और आपूर्ति शृंखला में बाधाओं के कारण विदेशों से आयात होने वाले कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू मांग और उपलब्धता के बीच असंतुलन के कारण ऐन बुवाई के समय सोसायटियों और दुकानों पर स्टॉक खत्म हो जाता है। एनपीके जैसी जटिल खादों की कीमतों में हाल ही में लगभग 200 से 400 प्रति बोरी की वृद्धि दर्ज की गई है, जो यूरिया और डीएपी की महंगाई का संकेत है। सही समय पर खाद न मिलने के कारण कई राज्यों में अव्यवस्था, किसानों के बीच झड़प और कालाबाजारी की शिकायतें बढ़ रही हैं। खाद महंगे होने से छोटे और सीमांत किसानों का कृषि बजट बिगड़ रहा है। समय पर उर्वरक (डीएपी, यूरिया) न मिलने से रबी और खरीफ़ दोनों फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल और ईंधन की कीमतों में भारी उछाल के कारण देश में खाद (यूरिया, डीएपी, एनपीके) का गहराता संकट एक बड़ी चुनौती बन गया है। किसानों को बुवाई के समय लंबी लाइनों में लगने और बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम एशिया के तनाव और आपूर्ति शृंखला में बाधाओं के कारण विदेशों से आयात होने वाले कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू मांग और उपलब्धता के बीच असंतुलन के कारण ऐन बुवाई के समय सोसायटियों और दुकानों पर स्टॉक खत्म हो जाता है। एनपीके जैसी जटिल खादों की कीमतों में हाल ही में लगभग 200 से 400 प्रति बोरी की वृद्धि दर्ज की गई है, जो यूरिया और डीएपी की महंगाई का संकेत है। सही समय पर खाद न मिलने के कारण कई राज्यों में अव्यवस्था, किसानों के बीच झड़प और कालाबाजारी की शिकायतें बढ़ रही हैं। खाद महंगे होने से छोटे और सीमांत किसानों का कृषि बजट बिगड़ रहा है। समय पर उर्वरक (डीएपी, यूरिया) न मिलने से रबी और खरीफ़ दोनों फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है। यह अस्थिर है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति में कठिनाई और उनके मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार न खेत बनाओ अभियान शुरू किया। इस अभियान को शुरू करने के पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों और किसान संगठनों से गहरा संवाद किया, उससे यह होता चलता है कि वे इस अभियान को वास्तव में सफल बनाए हुए देखना चाहते हैं। ऐसे किसी अभियान की सफलता जन भागीदारी और जागरूकता के माध्यम से ही संभव है। नि:संदेह इस अभियान में केंद्र सरकार को राज्यों का सक्रिय सहयोग चाहिए होगा।

